

संपादकीय

आरथण की सच्चाई

अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के उपर्योगकरण की संभवनाओं का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की ओर से मिले सकेत यदि यह रेखांकित कर रहे हैं कि ओवीसी आरक्षण का लाभ चुनिदा जातियों ने उठाया है तो इसमें हरानी नहीं। इस स्थिति को बयान करने वाले आंकड़े उपलब्ध भले न हों, लेकिन हर कोई यह जान रहा है कि हकीकत यह है। यह विसंगति केवल ओवीसी आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। यही हालत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिले आरक्षण में भी है। अब जब ओवीसी आरक्षण में उपर्योगकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि एससी-एसटी आरक्षण में भी ऐसा हो। नीति-नियतों और राजनीतिक दल इससे अनभिन्न नहीं हो सकते कि यह आरक्षण में विसंगति अधिक सभी पात्र जातियों को सम्मुचित लाभ न मिल पाने का ही प्रतिफल है कि जहाँ ओवीसी की कुछ जातियों अनुसूचित जाति का दर्जा चाह रही है वही कुछ अनुसूचित जातियों जनजाति के दर्जा में अपनी गिनती कराना चाहती है। ओवीसी आरक्षण का अधिकतम लाभ उठाने वाली जातियों आमतौर पर वही हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत सक्षम हैं। इन्हें पिछड़े में अंगड़े की संज्ञा दी जा सकती है। अलग-अलग राज्यों में पिछड़े में अंगड़े का दर्जा रखने वाली जातियों तो राजनीतिक रूप से भी प्रभावी हैं। इसके चलते उनका शासन में भी दबदबा है और कहाँ-कहाँ तो प्रशासन में भी। इसका कोई मतलब नहीं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावी जातियों आरक्षण का लाभ उठाती रहें। 1 यदि समर्थ जातियों के लोग आरक्षण का लाभ लेते रहें तो वे कहाँ न कहाँ अन्य ऐसी जातियों के अधिकारों का हरण ही करेंगे जो आरक्षण के दायरे में होने के बावजूद उपर्युक्त लाभ से विचित हैं। समय आ गया है कि न केवल ओवीसी आरक्षण के तहत आने वाली जातियों का उपर्योगकरण हो, बल्कि उन जातियों को आरक्षण के दायरे से अलग भी किया जाए जो अब आरक्षण का पात्र नहीं रह गई है। हालांकि ओवीसी लेपर की व्यवस्था इसी मकसद से की गई है, लेकिन उससे अंगड़े की पूर्ति नहीं हो या रही है। पता नहीं ऐसी कोई व्यवस्था एसटी-एसटी आरक्षण में क्यों नहीं है? जैसे यह एक तथ्य है कि भारतीय समाज को समसर बनाने के लिए आरक्षण की अवधिकरता है वैसे ही यह भी कि इस व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं। आरक्षण का लाभ कुछ समर्थ जातियों के खाने में जान केवल एक विसंगति है। 2 अन्य विसंगतियों की वर्चा इसलिए नहीं होती है। विडबन यह है कि वे आरक्षण की अपनी माम नवाने के लिए दिसंक तौर-तरीके भी आने रही हैं। बहर हो कि ओवीसी जातियों के उपर्योगकरण की दिशा में अगे बढ़ने के साथ ही आरक्षण की बढ़ती मांगों का भी कोई समाधान निकालने की कोशिश हो। यह कोशिश सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत ही होनी चाहिए।

बयान पर बेवजह विवाद

साधारण / कुमार नरेन्द्र सिंह

चंद दिनों पहले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत के बंटवारे के लिए जावाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बता कर एक अनवश्यक विवाद पैदा कर दिया है। दलाई लामा का कहना है कि गांधी जी मोहम्मद अंती जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू को यह स्वीकार नहीं था, जिसके चलते देश का बंटवारा हुआ। वैसे यह कोई पहली बार नहीं है, जब भारत के बंटवारे के लिए नेहरू को जिम्मेदार बताया जा रहा है।

सच तो यह है कि आजादी के बाद से ही अनेक संगठन और लोग, जिसमें कतिपय देशी-विदेशी विदान भी शामिल हैं, बंटवारे का दिवारा नेहरू के सर पर फोड़ते रहे हैं। यह अलग बात है कि किसी ने भी अंतिम रूप से इसे सिद्ध नहीं किया है। जिन्हें भी तर्क और तर दिए जाते हैं, वे विश्लेषणात्मक और बात से बात निकालने की क्यायदा ही नजर आते हैं दलाई लामा का ताजा बयान इस भौजपुरी कहावत को करते रहे जान आता है कि 'जेंगरा खातिर चोरी कहली उठे कहे दोरा यानी जिसके लिए चोरी की वही अब वार बता रहा है। आज दलाई लामा की जो हैसियत है, वह मूल रूप से नेहरू की समझदारी और दया का ही प्रतिफल है। बहरहाल, दलाई लामा के बयान को दो स्तरों पर परखने की जरूरत जान पड़ती है तात्पत्तक और राजनीति जन्य। प्रथम नजर में उनका बयान उस राजनीति का हिस्सा नजर आता है, जिसके अंतर्गत नेहरू को एक खलनायक के रूप में तब्दील करने की साजिश भरी कोशिश चल रही है। वैसे आजादी के पहले से ही कतिपय संगठन इस काशिंग में जुटे हुए हैं। संघ परिवार इस काशिंग का प्रथम और प्रबल प्रणाली रखता है। यूंके पिछले चार साल से देश की सत्ता पर उसी के राजनीतिक फंट यानी भारतीय जननाम पार्टी काबिज है, इसलिए शरणार्थी के रूप में रह रहे दलाई लामा को कई कारणों से आज उसकी ज्यादा जरूरत हो सकती है और ही है। ऐसे में यदि कोई कहता है कि ताजा बयान के पीछे दलाई लामा का मकसद वर्धमान सरकार की सदिच्छा और सहयोग पाने की मंशा से दिया गया है, तो उसे वर्योंकर गलत करता दिया जा सकता है। वैसे भी दलाई लामा कोई इतिहासकार नहीं है कि उनकी बात को ज्यादा तबज्जो दी जाए। बेहतर होगा कि वह केवल दलाई लामा ही बनें रहें। इस बात से इकाकर नहीं किया जा सकता कि महात्मा गांधी ने 1 अप्रैल, 1947 को तकालीन गवर्नर जनरल टॉफ मार्टिवेट को ताहा का था कि वह जिन्होंने को प्रधानमंत्री बनाए जाने का प्रस्ताव दिया थे, जिसे सुनकर सर्व यात्रीहासिक भी स्वाक्षर थे। लेकिन साथ में उन्होंने यह शर्त भी जोड़ी थी कि उनकी अगुआई में केवल मुस्लिम लोग सरकार बनाए और उसमें कांग्रेस शामिल नहीं होंगा, वह केवल सहयोग करेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सबसे पहले इस प्रस्ताव को ख्याल जिन्होंने ने ही खारिज किया था। जहाँ तक नेहरू की बात है तो उनकी आपत्ति इस बात पर भी कि मुस्लिम लोग देश के सभी मुसलमानों की प्रतिनिधि पार्टी होने का दावा नहीं कर सकती। इन्होंने तो यह किया था। यह नहीं करता वही उभरती है कि एस दोनों सवालों का उत्तर यही दिया जाना चाहता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक तकालीन गवर्नर जनरल ने यह किया था कि एस करने की विशेष निर्णयों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न तो व्यावहारिक था और न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक मुस्लिम लोग जी बात है, तो वह शुरू से ही मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ था। उसने 1940 में ही कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आजादी के बाद भारत के बंटवारे की वायंजान बताई थी। इसे में यदि कोई कहता है कि एस करने की विशेषताएँ एक मद्देनजर कंडू में एक कमज़ोर सरकार व्यावहारिक था? दूसरा कि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक तकालीन गवर्नर जनरल ने यह किया था कि एस करने की विशेष निर्णयों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक मुस्लिम लोग जी बात है, तो वह शुरू से ही मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ था। उसने 1940 में ही कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आजादी के बाद भारत के बंटवारे की वायंजान बताई थी। इसे में यदि कोई कहता है कि एस करने की विशेषताएँ एक मद्देनजर कंडू में एक कमज़ोर सरकार व्यावहारिक था? दूसरा कि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक तकालीन गवर्नर जनरल ने यह किया था कि एस करने की विशेष नि�र्णयों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक मुस्लिम लोग जी बात है, तो वह शुरू से ही मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ था। उसने 1940 में ही कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आजादी के बाद भारत के बंटवारे की वायंजान बताई थी। इसे में यदि कोई कहता है कि एस करने की विशेषताएँ एक मद्देनजर कंडू में एक कमज़ोर सरकार व्यावहारिक था? दूसरा कि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक तकालीन गवर्नर जनरल ने यह किया था कि एस करने की विशेष नि�र्णयों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आशका नहीं उभरती? इन दोनों सवालों का उत्तर यही हो सकता है कि एस करना न वांछनीय। मालूम हो जी की पूरी तरह राष्ट्र की साथ थे। जहाँ तक मुस्लिम लोग जी बात है, तो वह शुरू से ही मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ था। उसने 1940 में ही कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें आजादी के बाद भारत के बंटवारे की वायंजान बताई थी। इसे में यदि कोई कहता है कि एस करने की विशेषताएँ एक मद्देनजर कंडू में एक कमज़ोर सरकार व्यावहारिक था? दूसरा कि तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के बाद क्या देश की अखंडता के लिए खतरे की आश

